

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी—संजय शर्मा

अपील संख्या 57 / 2022

तारीख रजू 18.10.2022

रामस्वरूप पुत्र भोला जाट निवासी अक्षयगढ, तहसील खण्डार ।

---- अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार खण्डार ।
उपस्थिति —

---- रेस्पोजेन्ट

श्री मोहम्मद इमरान खान एडवोकेट
पेरोकार राजस्व

— अपीलार्थी
— रेस्पोजेन्ट

निर्णय

दिनांक 08.08.2025

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार खण्डार द्वारा मिसल संख्या 02 / 2022 में पारित आदेश दिनांक 26.07.2022 के विरुद्ध प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को पटवार मण्डल अक्षयगढ के राजस्व ग्राम अक्षयगढ के आराजी खसरा नम्बर 291 रकबा 0.03 बीघा किस्म गै0मु0 रास्ता पर संवत् 2079 में जिन्स जोत कर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने का कर्ता मानकर अतिक्रमणित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए तीन माह (90) दिवस के सिविल साधारण कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोजेन्ट की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलार्थी निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोजेन्ट की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलार्थी आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में कथन किया कि लायक अदालत मातहत का निर्णय विधि विरुद्ध एवं रिकार्ड के विपरीत होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की बिलकुल गलत एवं निराधार रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी को नोटिस जारी कर बिना अपीलार्थी की तामील हुए तथा अपीलार्थी को जवाबदेही एवं सबूत पेश करने का मौका दिये बिना ही विवादित निर्णय पारित कर भारी कानूनी भूल की है जो खारिज होने योग्य है। अपीलार्थी द्वारा आराजी ख0नं0 291 रकबा 0.03 बीघा किस्म गै0मु0 रास्ता पर जिन्स जोतकर संवत् 2079 में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है जो कि बिलकुल गलत एवं निराधार है। अपीलार्थी ने उक्त आराजी पर कोई जिन्स जोत कर गै0मु0 रास्ता भूमि पर कब्जा नहीं किया है बल्कि मोके पर सडक मौजूद है तथा अपीलार्थी का उक्त भूमि से किसी भी प्रकार का ताल्लुक या वास्ता नहीं है, फिर भी पटवारी हल्का ने गलत रिपोर्ट करके साजिश वश अपीलार्थी को उक्त मुकदमे में मुलव्विस कर दिया है जो निरस्त होने योग्य है। विवादित आराजी राज्य सरकार के नाम दर्ज है तथा किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज है इसलिये उक्त भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा करने का सवाल ही नहीं उठता और उक्त भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा नहीं है ना ही कोई फसल काश्त की है ना ही पटवारी हल्का ने पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने का कोई


अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

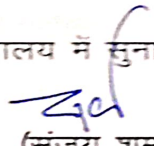

सबूत ही पेश किया है इसलिए अदालत मातहत का निर्णय निरस्त होने योग्य है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.07.2022 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए परोकार सरकार ने बहस में कथन किया कि अपीलार्थी को विधिवत नोटिस जारी करने के पश्चात ही अपीलार्थी को सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने व पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित हो जाने के पश्चात ही अपीलार्थी निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है। परोकार ने बहस में यह भी तर्क दिया है कि विवादित भूमि की किस्म गै0मु0 रास्ता है जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है तथा आम जन के आवागमन के काम आती है यदि अपीलार्थी को सार्वजनिक उपयोग की भूमि से वेदखल नहीं किया गया तो अन्य व्यक्तियों को भी अतिक्रमण करने हेतु बढ़ावा मिलेगा। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलार्थी निर्णय की पत्रावली का अवलोकन करने से यह प्रतीत होता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अपीलार्थी को धारा 91 का नोटिस जारी किया गया है जिस पर अपीलान्ट के पुत्र की तामील हुई है। बावजूद तामील अपीलान्ट नियत दिनांक को जानबूझ कर अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अतः अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का समुचित अवसर दिया गया है। जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है इसकी पुष्टि भी पत्रावली पर उपलब्ध विधिक साक्ष्य यथा पटवार हल्का के लिये गये बयानों के आधार पर हो जाती है। चूंकि अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमित की गयी भूमि के संबंध में अपने पक्ष में इस प्रकार का कोई सुदृढ अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है, जिसके आधार पर विवादित भूमि पर अपीलान्ट का पूर्ववर्ती अतिक्रमण साबित नहीं होता हो। यद्यपि, अपीलान्ट ने उक्त आराजी ख0नं0 291 रकबा 0.03 बीघा गै0मु0रास्ता पर आज तक कभी कब्जा नहीं रहने और नाही संवत् 2079 में कोई काश्त करने का शपथ पत्र पेश किया है, अपीलान्ट द्वारा शपथ पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके कि अपीलान्ट उक्त आराजी ख0नं0 291 रकबा 0.03 बीघा गै0मु0रास्ता पर पूर्ववर्ती कब्जा नहीं रहा हो। यहां इस बात को भी नजर-अंदाज नहीं किया जा सकता है कि अतिक्रमित आराजी की किस्म गै0मु0रास्ता है जो आमजन के आवागमन में काम आता है व सार्वजनिक उपयोग की भूमि होने से उक्त भूमि पर बढ़ते अतिचार को रोकना अत्यन्त आवश्यक है। अदालत मातहत द्वारा पारित किये गये निर्णय में किसी प्रकार की अनियमितता नजर नहीं आती है तथा अपील अपीलान्ट खारिज योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 26.07.2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08.08.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(संजय शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर